(ग) चयन सूची में शामिल 119 अधिकारी अक्तूबर 1974 में पदोन्नत किये गये । चयन सूची के अन्त में जो शेष 3 अधिकारी थे वे सभोगवश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के थे, और उस समय रिक्त स्थान न होने के कारण उनको अन्य अधिकारियों के साथ-साथ पदोन्नत नहीं किया जा सका । अब रिक्त स्थान उपलब्ध हैं, किन्तु इन अधिकारियों को, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक अकेले न्यायाधीश के उस निर्णय को ध्यान में रखकर, पदोन्नत नहीं किया जा सकता जिसके अन्तर्गत उक्त चयन सूची को रद्द कर दिया गया है । सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध एक रिट अपील और निर्णय के प्रवर्तन के विरुद्ध स्थगन आदेश के लिए एक याचिका दायर की है जो उस न्यायालय की डिवीजन बैंच के सामने विचाराधीन हैं ।

एयर इंडिया एम्पलाइज गिल्ड द्वारा बोनस तथा महंगाई भत्ते की मांग

4449. **श्री अलेश्वर सिंह** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि एयर इंडिया एम्प्लाईज गिल्ड ने कर्मचारियों के लिये बोनस और महंगाई भत्ते की मांग की है ,

(ख) क्या एयर इंडिया के चेयरमैन श्री जे० आर० डी० टाटा ने इस बात को अस्वीकार किया है कि वर्ष 1973-74 में कर्मचारियों द्वारा उक्त निगम की उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है ,

(ग) क्या इस स्वीकृति के बाद भी कर्मचारियों की उक्त मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है , और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (घ) एयर इंडिया एम्प्लाईज गिल्ड (ए० आई० ई० जी०) एक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है । कुछ मांगों पर जिनमें बोनस की भी एक मांग सम्मिलित थी, दो मान्यता-प्राप्त यूनियनों—एयर कारपोरेशन एम्प्लाईज यूनियन (ए० सी० ई० यू०) तथा इंडियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन्स एसोसियेशन (आई०ए०टी०ए०) के साथ बातचीत की गयी थी तथा वर्ष 1970-71 के लिए बोनस के सबन्ध से 26 सितम्बर, 1972 को उनके साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए । फिर ए०आई०ई०जी० ने उसी वर्ष के लिए बोनस की मांग को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), बम्बई के सामने उठाया । एयर इंडिया के प्रबन्धक वर्ग ने क्षेत्रीयश्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ए०सी० यू० तथा आई०ए०टी०ए० के साथ हुए समझौतों से अवगत कराया तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने गिल्ड को समझौते के अन्तर्गत इस मांग को स्वीकार करने से अपनी असमर्थता प्रकट की ।

विभिन्न समझौतों की समाप्ति के पश्चात् दो मान्यता-प्राप्त यूनियनों अर्थात् ए०सी०ई०यू० तथा आई०ए०टी०ए० से प्रबन्धवर्ग को मार्च, 1973 में एक मांग-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण की मांग भी सम्मिलित थी, तथा कर्मचारियों के कुछ वर्गों को 1 अप्रेल, 1973 से अन्तरिम सहायता प्रदान की गयी । उसके पश्चात्, 1 अप्रेल, 1974 से इन यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व-प्राप्त समस्त कर्मचारियों को इस शर्त पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया गया कि 31 मार्च, 1975 तक किसी अन्य मांग पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(ख) जी, नहीं । चेयरमैन ने कारपोरेशन की वर्ष 1973-74 की वार्षिक रिपोर्ट में जो कुछ कहा है वह यह था कि वर्ष 1973-74 के दौरान प्रति कर्मचारी ए०टी०के०एम० (उपलब्ध टन किलोमीटर) वर्ष 1972-73 के दौरान 88,000 ए०टी०के०एम० की तुलना में 90,900 ए०टी० के०एम० थे और यह स्पष्ट किया गया है कि ए०टी०के०एम० में 1972-73 के मुकाबले 12 3 प्रतिशत की यह वृद्धि मुख्यतया बाइंग 747 के उपयोग में सुधार करके प्राप्त की गयी थी ।

Impact of Anti-Smuggling Drive on Prices

4450 SHRI JYOTIRMOY BOSU. Will the Minister of FINANCE be pleased to

refer to the reply given to Starred Question No 61 on the 21st February, 1975 regarding 'Impact of anti-smuggling drive on prices' and state

(a) the names of commodities whose prices have substantially gone down since the beginning of anti-smuggling drive, State-wise, and the extent of decline in retail prices in each commodity; and

(b) from which source or sources the data relating to the impact of anti-smuggling drive on prices has been gathered?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) (a) In reply to Starred Question No 61 on 21 2-75 it had been stated that the anti smuggling measures coupled with other anti-inflationary measures taken by Government have produced a wholesome effect on the general price level which has shown some decline The wholesale price index (in 1961-62 = 100) which had touched the peak level of 330 4 for the week ended September 21st 1974 had fallen to 309 2 on 1 3-75 The consumer price index (1960 = 100) fell from 334 in September 1974 to 326 in December, 1974

On account of multiplicity of markets and price variation arising from difference in variety quality etc, it is not feasible to supply information state wise commodity wise, regarding the decline in retail prices

(b) The wholesale price index is compiled by the Office of the Economic Adviser Ministry of Industry & Civil Supplies, and the consumer price index is compiled by the Labour Bureau, Simla which is under the Ministry of Labour

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ता

4452 श्री विभूति मिश्र क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1975 के "दि इंडियन एक्सप्रैस" के पृष्ठ 1, स्तम्भ (कालम) 2 में "मोर डी० ए० फार आर० बी० आई० आफिसर्स" (भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों के लिए अधिक महंगाई भत्ता) शीर्षक, के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के वेतन तथा भत्तों के सबन्ध में कोई दोष रहित सिद्धान्त निर्धारित किया है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) सरकार ने उल्लिखित समाचार का देखा है।

(ख) और (ग) इस मामले में राज्य सरकारों का अपनी स्वयं की नीति है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का सबन्ध है इन मामलों पर केन्द्रीय सरकार उसके द्वारा स्थापित वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर निर्णय करती है।

Modification By R B I. Regarding Credit Policy to Facilitate Production of Goods of Mass Consumption

4455 SHRI ARJUN SETHI Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether recently there has been any modification by the Reserve Bank of India regarding the credit policy with a view to facilitating the production of goods of mass consumption

(b) if so the broad outlines regarding the revised policy of Government, and

(c) steps taken to ensure that the increased credit facilities are not misused for hoarding goods of mass consumption?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) (a) and (b) While announcing the credit policy measures for the 1974-75 busy season on the 29th October, 1974, Reserve Bank had im-